डबल इंजन की सरकार

कितनी बदली जिंदगी

आर्थिकी को रफ्तार

केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के तीन साल बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो जनमानस के दिमाग में पहला सवाल यही थी कि अब क्या फर्क आएगा। यह फर्क सात साल बाद बहुत कुछ स्पष्ट होने लगा है। केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत की है तो विकास योजनाएं भी धरातल पर हैं। जीवन कितना सुगम हुआ, बता रहे हैं राज्य ब्यूरो के विशेष संवाददाता राजीव दीक्षित...

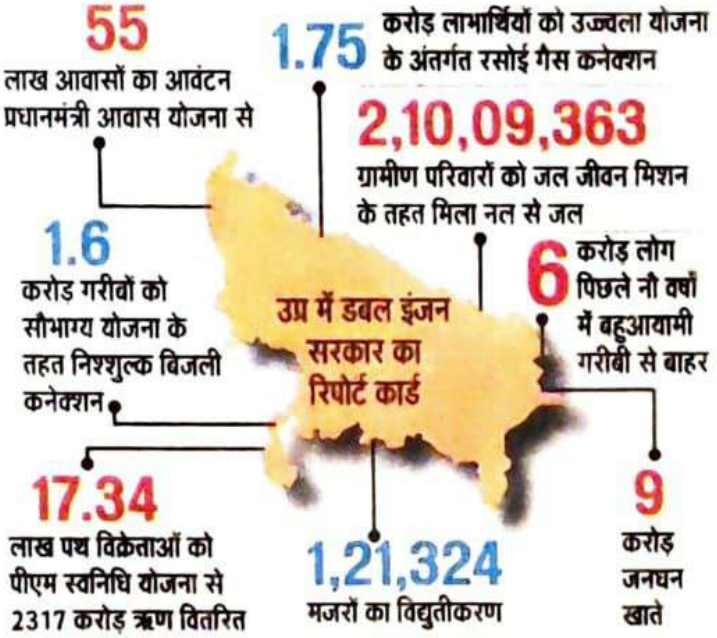

मुंबई में बीते कई वर्षों से रह रहे होम एप्लायंसेज बनाने वाली एक प्रतिष्ठित कंपनी के बड़े ओहदेदार बीते दिनों लखनऊ आए थे। यहां से वह सड़क मार्ग से अपनी ननिहाल कन्नौज गए। फिर लखनऊ वापसी कर सड़क मार्ग से ही अपने गृह जिले वाराणसी भी गए। इस दौरान वह आगरा-लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों से गुजरे तो फोर लेन हाईवे पर भी उनकी टैक्सी दौड़ी। लखनऊ आकर मित्र से उन्होंने बेसाख्ता कहा कि 'उप्र की सड़कें तो महाराष्ट्र को मात दे रही हैं।'

इस वाकये का जिक्र इसलिए क्योंकि उप्र का नाम आते ही जेहन में 'गड्ढों में सड़क' वाली छवि उभरती है, लेकिन ऐसे कड़े अनुभव के दिन अब लद गए। बसपा सरकार में बने यमुना एक्सप्रेसवे और अखिलेश राज में तैयार हुए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के अलावा अब पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी उप्र की सरजमीं की शोभा बढ़ा रहे हैं। मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए 603 किमी लंबा गंगा एक्सप्रेसवे के अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया एक्सप्रेसवे का निर्माण जारी है। देश की कुल एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की लंबाई का 55 प्रतिशत हिस्सा उप्र में है। वर्ष 2017 से पहले के पांच वर्षों में प्रदेश में जहां 15 हजार किमी सड़क का निर्माण किया जा सका था, वहीं 2017 में योगी सरकार के आने के बाद 31 दिसंबर 2022 तक ही 19 हजार किमी से अधिक सड़क निर्माण हो चुका था। एयर कनेक्टिविटी में भी उप्र ने उड़ान भरी है। लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और अयोध्या समेत अब उप्र चार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला प्रदेश बन गया है। जेवर एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने पर सूबे में पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे।

बेशक उप्र को एक ट्रिलियन डालर के आकार की अर्थव्यवस्था बनाने की मंजिल अभी दूर है, लेकिन बुनियादी ढांचे की मजबूती और दुरुस्त की गई कानून व्यवस्था ने उप्र की आर्थिकी को भी रफ्तार दी है। बीते 10 वर्षों के दौरान उप्र में प्रति व्यक्ति आय दोगुणी हुई है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से नागरिकों की क्रय शक्ति बढ़ी है। डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में उप्र निवेश के बड़े गंतव्य के रूप में उभरा है। फरवरी 2018 में आयोजित यूपी इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से जहां 4.28 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव राज्य सरकार को मिले थे तो गत वर्ष फरवरी में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से लेकर अब तक 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव सरकार को हासिल हुए थे। इसमें से 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को पिछले माह राजधानी में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से धरातल पर उतारा गया। उप्र में इतने बड़े पैमाने पर निवेश की इच्छा जताने की परिकल्पना 2017 से पहले अकल्पनीय थी।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ डबल इंजन की सरकार का जोर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के जरिये आम जन को मकान, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराकर जीवन को सुगम बनाने पर भी है। 'सबके सर पर छत' की परिकल्पना को साकार करने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-17 तक मात्र 12 हजार मकान स्वीकृत किए गए जबकि 2017 से अब तक प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 55 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं।

सांझ ढलने पर अंधेरे के अभिशाप से 1.21 लाख मजरे विद्युतीकरण के जरिये मुक्त किए गए तो सौभाग्य योजना बड़े पैमाने पर वंचितों-गरीबों को निशुल्क बिजली कनेक्शन देने का माध्यम बनी। वर्ष 2012-17 तक प्रदेश में आठ लाख बिजली कनेक्शन ही दिए जा सके थे। प्रदेश की पौने दो करोड़ महिलाओं को खाना बनाने के लिए लकड़ी और कंडे जलाने की जिद्दोजहद से निजात मिली। रोज कुंआ खोदकर पानी पीने वाले रेहड़ी-पटरी दुकानदारों के जीवन को आर्थिकी की राह पर संबल देने में पीएम स्वनिधि योजना की भूमिका भी रही है। जीवन को सुगम बनाने की इन्हीं कोशिशों का नतीजा रहा है कि पिछले नौ वर्षों के दौरान उप्र में छह करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए हैं।

विकास परियोजनाओं और औद्योगिकीकरण के जरिये प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने की राह पर आगे बढ़ाने के मौजूदा निजाम के दावे कितने पुख्ता हैं, लोकसभा चुनाव में मतदाता इसका आकलन करेंगे।